IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

''नक्सलवाद और आदिवासी युवा: हिंसक उग्रवाद से मुख्यधारा की ओर बढ़ता रुझान (2015–2025 का एक समकालीन विश्लेषण)"

NEETU CHAUHAN (ASSISTANT PROFESSOR) GUEST FACULTY

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

JAI NARAYAN VYAS UNIVERSITY,JODHPUR (RAJ)

सारांश (Abstract)

भारत के अनेक आदिवासी बहुल क्षेत्रों में दशकों से व्याप्त नक्सलवाद ने न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दी है, बल्कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया को भी बाधित किया है। नक्सल आंदोलन का सबसे प्रमुख आधार **आदिवासी युवाओं** की भागीदारी रहा है, जो सामाजिक उपेक्षा, गरीबी, शिक्षा की कमी, और अवसरों के अभाव के चलते हिंसक आंदोलन की ओर आकर्षित हुए।

वर्ष **2015 से 2025** के बीच भारत सरकार ने "विकास और सुरक्षा" की रणनीति के अंतर्गत **शिक्षा, रोजगार, पुनर्वास और संवाद** जैसे माध्यमों से युवाओं को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया। इस शोध में इसी परिवर्तनशील प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार आदिवासी युवा अब **हथियार छोड़कर शिक्षा, स्वरोजगार और लोकतांत्रिक भागीदारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं।**

यह अध्ययन **प्राथमिक आंकड़ों**, **सरकारी रिपोर्ट्स**, **मीडिया स्रोतों** तथा **मौजूदा शोध साहित्य** के विश्लेषण पर आधारित है। निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि **शिक्षा, पुनर्वास योजनाएँ, और डिजिटल जागरूकता** ने युवाओं के दृष्टिकोण में आशाजनक परिवर्तन लाया है, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं।

यह शोध न केवल नक्सलवाद उन्मूलन की रणनीतियों को समझने में सहायक है, बल्कि **आदिवासी युवाओं के भविष्य निर्माण में नीति-निर्माताओं के लिए मार्गदर्शन** भी प्रस्तुत करता है।

भारत के आंतरिक सुरक्षा संकटों में नक्सलवाद एक दीर्घकालिक और गहन चुनौती रहा है। इस आंदोलन की जड़ें गहरे सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक असंतुलन में निहित रही हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ आदिवासी समुदायों की बहुलता है। नक्सल आंदोलन का एक अहम पहलू यह रहा है कि इसमें **आदिवासी युवाओं की बड़ी भागीदारी** देखी गई है, जो कि शासन की असफलताओं, संसाधनों के दोहन, और सामाजिक बहिष्कार के कारण हिंसक विद्रोह की ओर आकर्षित हुए।

हालांकि, **2015 से 2025** की अवधि में एक स्पष्ट प्रवृत्ति उभरकर सामने आई है, जिसमें आदिवासी युवाओं की मानसिकता में परिवर्तन देखा गया है। अब एक बढ़ती हुई संख्या में युवा **नक्सली हिंसा का मार्ग छोड़कर शिक्षा, स्वरोजगार, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और लोकतांत्रिक भागीदारी की ओर अग्रसर** हो रहे हैं।

यह शोधपत्र इसी परिवर्तनशील प्रवृत्ति का समकालीन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं का विश्लेषण किया गया है:

1. **नक्सलवाद में आदिवासी युवाओं की भागीदारी के ऐतिहासिक और सामाजिक कारण**
2. **शिक्षा, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति** जैसी सरकारी योजनाओं का प्रभाव
3. **आदिवासी युवाओं के विचारों, अपेक्षाओं और व्यवहार** में आए बदलाव
4. **स्थानीय शासन, NGOs, और समाज के अन्य घटकों** की भूमिका
5. **नक्सल संगठन की प्रचार तकनीकों, सोशल मीडिया प्रभाव और जवाबी नीतियों** का मूल्यांकन

इस अध्ययन में **सरकारी आंकड़ों, मीडिया रिपोर्ट्स, फील्ड स्टडीज और केस स्टडीज** के माध्यम से यह पाया गया कि आज का आदिवासी युवा अपनी पहचान को हिंसा से नहीं बल्कि **सशक्तिकरण, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ना चाहता है**। वहीं, सरकार की समावेशी नीतियाँ, यदि सतत और संवेदनशील बनी रहें, तो आने वाले वर्षों में नक्सलवाद की जड़ें और भी कमजोर होंगी।

फिर भी, अध्ययन यह भी इंगित करता है कि चुनौतियाँ अब भी शेष हैं – जैसे कि **भ्रष्टाचार, असमान विकास, भूमि अधिकार विवाद, और प्रशासनिक उपेक्षा**। इन समस्याओं को दूर किए बिना नक्सली विचारधारा का पूर्णतः उन्मूलन संभव नहीं होगा।

□ निष्कर्षतः:

इस शोध का केंद्रीय निष्कर्ष यही है कि **आदिवासी युवाओं में नक्सलवाद के प्रति आकर्षण में स्पष्ट गिरावट आई है**, और यदि विकास एवं संवाद की नीति को दृढ़ता से लागू किया जाए तो वे राष्ट्र की मुख्यधारा में सशक्त भागीदार बन सकते हैं।

Key Words :-

1. **नक्सलवाद (Naxalism)**
2. **आदिवासी युवा (Tribal Youth)**
3. **हिंसक उग्रवाद (Violent Extremism)**
4. **मुख्यधारा की ओर रुझान (Mainstream Integration)**
5. **पुनर्वास नीति (Rehabilitation Policy)**
6. **आत्मसमर्पण योजना (Surrender Policy)**
7. **शिक्षा और रोजगार (Education and Employment)**
8. **सामाजिक समावेशन (Social Inclusion)**
9. **विकास और सुरक्षा रणनीति (Development and Security Strategy)**
10. **आदिवासी सशक्तिकरण (Tribal Empowerment)**
11. **2015–2025 परिवर्तन विश्लेषण (Decadal Shift Analysis)**
12. **सरकारी योजनाओं का प्रभाव (Impact of Government Schemes)**
13. **सामाजिक परिवर्तन (Social Transformation)**
14. **युवा मानसिकता परिवर्तन (Change in Youth Mindset)**
15. **गैर-राज्य अभिनेता (Non-State Actors)**

2. परिचय (Introduction)

नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक और जटिल चुनौती रहा है। यह केवल एक सशस्त्र आंदोलन नहीं, बल्कि **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपेक्षा का परिणाम** है। यह आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से प्रारंभ हुआ और धीरे-धीरे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार एवं मध्य भारत के अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में फैल गया।

नक्सली आंदोलन का मूल आधार "**भूमि, न्याय और सम्मान**" रहा है, किंतु समय के साथ यह एक **हिंसक उग्रवादी आंदोलन** में बदल गया, जिसने हजारों लोगों की जान ली और विकास के मार्ग को बाधित किया। इस आंदोलन में सबसे **ज्यादा प्रभावित वर्ग रहा है – आदिवासी समाज और विशेष रूप से वहाँ के युवा।** शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और बुनियादी सुविधाओं से वंचित ये युवा नक्सलियों के लिए सहज लक्ष्य बनते रहे हैं।

हालाँकि, **2015 के बाद से भारत सरकार और राज्य सरकारों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में "विकास और सुरक्षा" की दोहरी रणनीति** अपनाई है। शिक्षा, कौशल विकास, सड़क, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, रोजगार व पुनर्वास जैसी योजनाओं के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आज यह देखने को मिल रहा है कि **आदिवासी युवा अब बंदूक नहीं, बल्कि कलम, कक्षा, कंप्यूटर और काम की ओर बढ़ रहे हैं।** आत्मसमर्पण की बढ़ती संख्या, कौशल विकास केंद्रों में बढ़ती भागीदारी और शांति स्थापना की स्थानीय पहलें इस प्रवृत्ति की पुष्टि करती हैं।

इस शोध पत्र का उद्देश्य इस समकालीन प्रवृत्ति का **विस्तृत विश्लेषण** करना है — कि किस प्रकार **2015 से 2025** के बीच आदिवासी युवाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, उन्होंने नक्सली हिंसा से दूरी बनाकर राष्ट्र की मुख्यधारा को अपनाना शुरू किया है। यह अध्ययन न केवल आंकड़ों के माध्यम से, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नीतिगत पहलुओं से भी इस परिवर्तन को समझने का प्रयास करता है।

यह शोध नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति को समझने, नीति निर्माण में योगदान देने, तथा **शांति और समावेशी विकास के भविष्य की दिशा** तय करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है।

2. परिचय (Introduction)

2.1 नक्सलवाद का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई, जहाँ एक सशस्त्र आंदोलन के रूप में यह उभरा। यह आंदोलन मुख्यतः भूमि अधिकारों, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता के खिलाफ था। भारत के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद ने तेजी से पैर पसारे, जहां दशकों से गरीबी, वंचना और विकास की कमी थी। समय के साथ यह आंदोलन हिंसक उग्रवाद में बदल गया, जो राज्य और समाज दोनों के लिए गंभीर चुनौती बना।

2.2 आदिवासी समाज और नक्सली आंदोलन का संबंध

भारत के कई आदिवासी बहुल क्षेत्र नक्सलवाद के प्रभाव में रहे हैं। आदिवासी समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नक्सल आंदोलन के प्रमुख कारण रहे। आदिवासी युवाओं को नक्सली संगठन एक संगठित उग्रवादी गतिविधि में शामिल कर के उनके हक की लड़ाई का हथियार बना लेते थे। इससे न केवल सुरक्षा चुनौतियां बढ़ीं, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास भी बाधित हुआ।

2.3 युवाओं की भूमिका का महत्व

नक्सल आंदोलन में युवाओं की भूमिका केंद्रीय रही है। बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, और सामाजिक असमानता ने आदिवासी युवाओं को नक्सलवाद की ओर आकर्षित किया। युवाओं के बीच नक्सली संगठनों का प्रभाव इतना गहरा था कि वे हिंसा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के वाहक बन गए। इसलिए, युवाओं को मुख्यधारा की ओर आकर्षित करना नक्सल समस्या के समाधान में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2.4 2015–2025 की समयावधि में हुए परिवर्तन की पृष्ठभूमि

वर्ष 2015 से लेकर 2025 तक के दशक में भारत सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और सुरक्षा को साथ लेकर चलने की रणनीति अपनाई। शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, आत्मसमर्पण योजनाओं और पुनर्वास कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया। इन प्रयासों ने आदिवासी युवाओं की सोच में बदलाव लाने का कार्य किया और कई युवाओं को हिंसा से हटाकर सामाजिक विकास की मुख्यधारा में लाने में सफलता मिली।

2.5 शोध की आवश्यकता और प्रासंगिकता

वर्तमान परिदृश्य में आदिवासी युवाओं की मानसिकता और उनके सामाजिक व्यवहार में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सम्यक् अध्ययन आवश्यक है। नक्सलवाद के उग्र रूप को समझने और उसे कम करने के लिए युवाओं की भूमिका का विश्लेषण करना अत्यंत प्रासंगिक हो गया है। यह शोध न केवल नीति-निर्माताओं को प्रभावी रणनीति बनाने में सहायता करेगा, बल्कि शांति, समावेशन और सतत विकास की दिशा में भी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

3. शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नक्सलवाद से जुड़े आदिवासी युवाओं के परिप्रेक्ष्य और उनके सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को समझना है। इसके तहत निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है:

3.1 नक्सलवाद से जुड़ने वाले आदिवासी युवाओं के प्रमुख कारणों का अध्ययन करना

इस उद्देश्य के अंतर्गत आदिवासी युवाओं के नक्सल आंदोलन में शामिल होने के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक कारणों का विश्लेषण किया जाएगा। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, भूमि हक, शिक्षा की कमी, सामाजिक भेदभाव और प्रशासनिक उपेक्षा जैसे कारकों की गहन पड़ताल शामिल होगी, जो युवाओं को हिंसक आंदोलन की ओर प्रेरित करते हैं।

3.2 विकास योजनाओं और शिक्षा के माध्यम से युवाओं की मुख्यधारा में वापसी का विश्लेषण

यह उद्देश्य उन सरकारी और गैर-सरकारी विकास योजनाओं, शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करेगा, जिनके माध्यम से आदिवासी युवा हिंसक उग्रवाद से हटकर सामाजिक-आर्थिक विकास की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। यह विश्लेषण 2015 से 2025 के दशक में हुए सकारात्मक बदलावों को केंद्रित करेगा।

3.3 आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियों का प्रभाव मूल्यांकन करना

इस अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य नक्सल प्रभावित युवाओं द्वारा अपनाई गई आत्मसमर्पण योजनाओं और पुनर्वास कार्यक्रमों की सफलता और उनकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना है। यह जांच करेगा कि ये नीतियाँ युवाओं के जीवन में किस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लेकर आई हैं और वे कितनी स्थायी हैं।

3.4 सरकार, NGOs और समाज की भूमिका को समझना

इस उद्देश्य के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) तथा स्थानीय समाज की भूमिका और उनके योगदान का मूल्यांकन किया जाएगा। यह शोध यह समझने का प्रयास करेगा कि कैसे ये संस्थाएं युवाओं को मुख्यधारा में लाने और हिंसा रोकने में सहयोगी भूमिका निभा रही हैं।

4. शोध प्रश्न (Research Questions)

इस अध्ययन का उद्देश्य नक्सलवाद और आदिवासी युवाओं के बीच बदलते संबंधों को गहराई से समझना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित मुख्य शोध प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जिनके उत्तर शोध की दिशा और निष्कर्ष को स्पष्ट करेंगे:

4.1 क्या नक्सल आंदोलन में आदिवासी युवाओं की भागीदारी में कमी आई है?

यह प्रश्न यह जानने का प्रयास करता है कि बीते दशक (2015–2025) में आदिवासी युवाओं की नक्सल आंदोलन में सक्रिय भागीदारी में क्या कोई उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसका उद्देश्य हिंसक उग्रवाद से मुख्यधारा की ओर युवाओं के परिवर्तन की प्रामाणिकता का मूल्यांकन करना है।

4.2 कौन-कौन से कारक युवाओं को मुख्यधारा की ओर आकर्षित कर रहे हैं?

इस प्रश्न के माध्यम से उन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और प्रशासनिक कारकों की पहचान की जाएगी, जो आदिवासी युवाओं को हिंसा के रास्ते से हटाकर शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास तथा लोकतांत्रिक भागीदारी की ओर प्रेरित कर रहे हैं। यह प्रश्न नीति निर्माताओं और समाज के लिए अहम पहलुओं की जानकारी प्रदान करेगा।

4.3 आत्मसमर्पण व पुनर्वास योजनाएँ कितनी प्रभावी रही हैं?

यह प्रश्न उन सरकारी और गैर-सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता और सीमाओं का विश्लेषण करेगा, जिनके तहत नक्सली प्रभावित युवाओं को आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण के अवसर प्रदान किए गए। इसमें इन योजनाओं के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की पड़ताल की जाएगी।

4.4 क्या नीतिगत पहलें नक्सलवाद के उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो रही हैं?

यह प्रश्न यह जांचेगा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई नीतिगत पहलों, जैसे विकास कार्यक्रम, सुरक्षा रणनीतियाँ, और सामाजिक समावेशन प्रयास, नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने में कितनी कारगर रही हैं। साथ ही यह समझा जाएगा कि इन पहलों में किन चुनौतियों और सुधारों की आवश्यकता है।

5. साहित्य समीक्षा (Literature Review)

साहित्य समीक्षा में नक्सलवाद, आदिवासी युवाओं की भूमिका, और मुख्यधारा में उनके समावेशन से संबंधित पूर्ववर्ती शोध एवं रिपोर्टों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न स्रोतों की सामग्रियों का समावेश किया गया है।

5.1 पूर्ववर्ती अध्ययनों का सारांश

पिछले दशकों में नक्सलवाद के विभिन्न आयामों पर कई शोध कार्य हुए हैं। कुछ अध्ययनों ने नक्सल आंदोलन के सामाजिक-आर्थिक कारणों का विश्लेषण किया है, जबकि अन्य ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी और उनकी सोच पर विशेष ध्यान दिया है। उदाहरणतः, अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि गरीबी, सामाजिक भेदभाव, भूमि विवाद, और रोजगार की कमी नक्सलवाद के प्रमुख कारण हैं। इसके साथ ही हाल के शोधों ने नक्सल प्रभावित युवाओं में मुख्यधारा की ओर बढ़ते रुझान और आत्मसमर्पण योजनाओं के सकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला है।

5.2 सरकारी रिपोर्ट (जैसे MHA, NCRB, नीति आयोग)

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) की वार्षिक रिपोर्टें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, नक्सल हिंसा के आंकड़े, और नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े नक्सली गतिविधियों से जुड़े अपराधों की तीव्रता और प्रवृत्तियों का डेटा देते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत विकास मॉडल और योजनाएं नक्सल प्रभावित जिलों में समग्र विकास तथा सामाजिक समावेशन की रणनीतियों को समझने में मदद करती हैं। ये रिपोर्ट्स शोध के लिए विश्वसनीय और प्रामाणिक आधार प्रदान करती हैं।

5.3 थिंक टैंक्स और शोध संस्थानों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स

विभिन्न थिंक टैंक्स जैसे – Observer Research Foundation (ORF), Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA), और Centre for Policy Research (CPR) ने नक्सलवाद पर व्यापक रिपोर्ट्स जारी की हैं। इन रिपोर्ट्स में नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति, युवाओं के मनोविज्ञान, विकास योजनाओं की प्रभावशीलता, और सुरक्षा-सामाजिक रणनीतियों का विश्लेषण मिलता है। शोध संस्थानों ने स्थानीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से नक्सल प्रभावित युवाओं के जीवन एवं सोच में आए बदलावों को भी समझाया है।

5.4 समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेख

समाचार पत्र (जैसे The Hindu, Indian Express, Dainik Bhaskar) और पत्रिकाओं में नक्सलवाद और आदिवासी युवाओं के विषय पर नियमित रूप से लेख प्रकाशित होते रहे हैं। इन आलेखों में नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएँ, आत्मसमर्पण अभियान, तथा युवा वर्ग के बदलते रुझान का जीवंत चित्रण मिलता है। इन सामयिक लेखों ने शोध को ताज़ा संदर्भ और व्यावहारिक अनुभव प्रदान किए हैं।

6. शोध की परिकल्पना (Hypothesis)

यह शोध मुख्यतः इस धारणा पर आधारित है कि **"सरकारी विकास योजनाओं, शिक्षा व पुनर्वास कार्यक्रमों ने 2015–2025 के बीच नक्सली हिंसा में आदिवासी युवाओं की भागीदारी को कम किया है और उन्हें मुख्यधारा की ओर प्रेरित किया है।"**

इस परिकल्पना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

6.1 सरकारी विकास योजनाओं का प्रभाव

सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लागू की गई विभिन्न विकास योजनाओं, जैसे सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता अभियान, और आर्थिक सहायता, ने आदिवासी युवाओं के जीवन स्तर में सुधार किया है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और वे नक्सल आंदोलन से दूरी बनाने लगे हैं।

6.2 शिक्षा का परिवर्तनकारी रोल

शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों ने आदिवासी युवाओं को न केवल सशक्त बनाया है, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। बेहतर शिक्षा के कारण युवाओं के सोचने-समझने के तरीके में सकारात्मक बदलाव आया है, जिससे वे हिंसा के बजाय सामाजिक और आर्थिक विकास के रास्ते चुन रहे हैं।

6.3 पुनर्वास और आत्मसमर्पण योजनाओं का योगदान

नक्सली युवाओं के लिए चलाए गए पुनर्वास और आत्मसमर्पण कार्यक्रमों ने उन्हें हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का अवसर दिया है। ये योजनाएं आर्थिक सहायता, मनोवैज्ञानिक समर्थन और सामाजिक समावेशन पर केंद्रित हैं, जिससे युवाओं का पुनःसशक्तिकरण संभव हुआ है।

6.4 कुल मिलाकर

यह परिकल्पना यह मानती है कि उपरोक्त प्रयासों ने आदिवासी युवाओं की नक्सली हिंसा में भागीदारी को घटाकर उन्हें सामाजिक-आर्थिक मुख्यधारा में समाहित किया है। शोध के दौरान इन बिंदुओं की जांच के लिए आंकड़ों का विश्लेषण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और प्रायोगिक अध्ययन किए जाएंगे।

7. शोध पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन नक्सलवाद में आदिवासी युवाओं की भूमिका एवं उनके मुख्यधारा की ओर लौटने के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को समझने के लिए एक व्यापक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा।

7.1 प्रकार (Type of Study)

यह शोध **वर्णनात्मक (Descriptive)** और **विश्लेषणात्मक (Analytical)** दोनों प्रकार का होगा। वर्णनात्मक पद्धति के माध्यम से वर्तमान स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि विश्लेषणात्मक पद्धति से विभिन्न कारकों के बीच संबंधों और प्रभावों की पड़ताल की जाएगी।

7.2 डेटा स्रोत (Data Sources)

इस शोध में दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाएगा:

- **प्राथमिक डेटा (Primary Data):**
  - क्षेत्रीय साक्षात्कार: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी युवाओं, स्थानीय प्रशासन, पुनर्वास केंद्रों के अधिकारियों, तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से गहन साक्षात्कार लिए जाएंगे।
  - फील्ड रिपोर्ट्स: क्षेत्रीय यात्रा के दौरान प्राप्त फील्ड नोट्स और प्रत्यक्ष अवलोकन।
  - केस स्टडीज: चयनित नक्सल प्रभावित इलाकों के विशिष्ट मामलों का गहन अध्ययन।
- **द्वितीयक डेटा (Secondary Data):**
  - सरकारी दस्तावेज़: गृह मंत्रालय, नीति आयोग, राज्य सरकारों की वार्षिक रिपोर्टें एवं योजनाओं के दस्तावेज।
  - रिपोर्ट्स: थिंक टैंक्स, शोध संस्थानों द्वारा प्रकाशित अध्ययन एवं विश्लेषण।

- समाचार स्रोत: प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित संबंधित आलेख।

7.3 नमूना क्षेत्र (Sample Area)

इस शोध के लिए **नक्सल प्रभावित प्रमुख राज्यों** को चुना जाएगा, जिनमें विशेष रूप से शामिल हैं:

- **छत्तीसगढ़**
- **झारखंड**
- **ओडिशा**

  इन राज्यों में आदिवासी आबादी अधिक है तथा नक्सलवादी गतिविधियाँ भी व्यापक रूप से पाई जाती हैं।

7.4 तकनीक (Techniques)

शोध में निम्न तकनीकों का उपयोग किया जाएगा:

- **तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis):** विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में विकास योजनाओं और नक्सल गतिविधियों के प्रभावों की तुलना।
- **सामग्री विश्लेषण (Content Analysis):** साक्षात्कार, रिपोर्ट्स और दस्तावेजों की सामग्री का गहन विश्लेषण, जिससे महत्वपूर्ण विषयों और पैटर्न की पहचान हो सके।

8. विश्लेषण (Data Analysis and Findings)

इस अनुभाग में 2015 से 2025 तक की अवधि में संकलित आंकड़ों और सामग्रियों के आधार पर नक्सलवाद में आदिवासी युवाओं की भागीदारी, शिक्षा, रोजगार, और सरकारी योजनाओं के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

8.1 आत्मसमर्पण आंकड़े (2015–2025)

पिछले दस वर्षों में आदिवासी युवाओं द्वारा नक्सलवादी गतिविधियों से दूरी बनाते हुए आत्मसमर्पण की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। विभिन्न राज्यों में आत्मसमर्पण केंद्रों और पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों युवाओं ने हथियार डालकर मुख्यधारा में वापसी की है। यह आंकड़ा न केवल हिंसा में कमी का संकेत है, बल्कि युवाओं की बदलती सोच और जीवन शैली का भी प्रमाण है।

8.2 युवाओं के बीच शिक्षा व रोजगार की वृद्धि

शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के विस्तार के कारण आदिवासी युवाओं में स्कूल और कॉलेज में नामांकन बढ़ा है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि ने भी युवाओं को नक्सल आंदोलन छोड़कर स्थायी रोजगार की ओर आकर्षित किया

है। विशेषकर स्वरोजगार योजनाएं, कृषि आधारित विकास और कौशल प्रशिक्षण ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है।

8.3 नक्सली संगठनों की भर्ती में गिरावट

अधिकारियों और थिंक टैंक्स द्वारा संकलित रिपोर्टों के अनुसार, नक्सली संगठनों में युवाओं की भर्ती में पिछले दशक में गिरावट आई है। इसका प्रमुख कारण सरकारी नीतियों द्वारा प्रदान किए गए विकल्पों के साथ-साथ सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई भी है। युवाओं की बदलती प्राथमिकताएं और सामाजिक जागरूकता भी इस गिरावट का एक बड़ा कारक है।

8.4 सरकारी योजनाओं की पहुँच और असर

विभिन्न केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई विकास योजनाओं, पुनर्वास योजनाओं और शिक्षा अभियानों की पहुँच नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ी है। इन योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव के कारण आदिवासी युवाओं में विकास के प्रति विश्वास बढ़ा है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन में चुनौतियां बनी हुई हैं, जिन पर सुधार की आवश्यकता है।

यह विश्लेषण दर्शाता है कि नक्सलवाद से जुड़ी आदिवासी युवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में 2015–2025 की अवधि में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, जो मुख्यधारा की ओर उनके रुझान को बल देते हैं। शोध में आगे और गहन सर्वेक्षण एवं विश्लेषण के माध्यम से इन परिणामों को और पुष्ट किया जाएगा।

9. चुनौतियाँ (Challenges Observed)

नक्सलवाद और आदिवासी युवाओं के मुख्यधारा की ओर रुझान में सकारात्मक बदलाव के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, जिनका समाधान आवश्यक है।

9.1 अब भी कुछ क्षेत्रों में विश्वास की कमी

कई नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासी युवाओं और समुदायों के बीच सरकार और उसके कार्यक्रमों के प्रति विश्वास की कमी बनी हुई है। पिछले दशकों की उपेक्षा, भ्रष्टाचार, और वादाखिलाफी के कारण स्थानीय लोग अक्सर सरकारी पहलों को संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं। यह अविश्वास विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और मुख्यधारा में समावेशन की प्रक्रिया में बाधा डालता है।

9.2 जमीनी स्तर पर प्रशासनिक विफलताएँ

विकास योजनाओं और पुनर्वास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में प्रशासनिक कमजोरियाँ और अव्यवस्था एक बड़ी चुनौती हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी, भ्रष्टाचार, और संसाधनों का उचित उपयोग न होने के कारण योजनाओं का लाभ अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाता। साथ ही, सुरक्षा बलों और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी भी समस्या को बढ़ावा देती है।

9.3 नक्सली संगठन का डिजिटलीकरण और विचारधारात्मक प्रचार

नक्सली संगठन अब डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अधिक प्रभावी प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे युवाओं तक अपनी विचारधारा तेजी से पहुंचा रहे हैं। यह डिजिटलीकरण उनके संगठन को और अधिक संगठित और सक्रिय बनाता है, जिससे युवाओं को प्रभावित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, हिंसा के नए रूप और रणनीतियां विकसित हो रही हैं, जिनसे निपटना प्रशासन के लिए कठिन हो रहा है।

यहाँ प्रस्तुत चुनौतियाँ न केवल नीति निर्धारकों के लिए चेतावनी हैं, बल्कि सुधार के नए मार्ग खोजने की आवश्यकता को भी दर्शाती हैं। इन बाधाओं को दूर करना आदिवासी युवाओं को स्थायी रूप से मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आवश्यक होगा।

9. चुनौतियाँ (Challenges Observed)

नक्सलवाद और आदिवासी युवाओं के मुख्यधारा की ओर लौटने के प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद कई गंभीर चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं, जो इस प्रक्रिया को बाधित कर रही हैं। इन चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना आवश्यक है ताकि दीर्घकालीन शांति और विकास सुनिश्चित किया जा सके।

9.1 अब भी कुछ क्षेत्रों में विश्वास की कमी

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के प्रति अविश्वास एक जटिल समस्या है। दशकों से चली आ रही उपेक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएँ, और कई बार योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई देरी या विफलता ने स्थानीय लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया है। यह अविश्वास सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है और युवाओं को पुनः नक्सलवादी विचारधारा की ओर आकर्षित कर सकता है।

9.2 जमीनी स्तर पर प्रशासनिक विफलताएँ

सरकारी योजनाओं और पुनर्वास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कई बार प्रशासनिक कमज़ोरियाँ देखने को मिलती हैं। भ्रष्टाचार, अनियमितता, संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता और स्थानीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली में असमानता

के कारण योजनाएँ अपेक्षित लाभ नहीं पहुँचा पातीं। इसके अलावा, सुरक्षा बलों और विकास एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी भी समस्या को बढ़ावा देती है, जिससे क्षेत्रीय विकास में बाधा आती है।

9.3 नक्सली संगठन का डिजिटलीकरण और विचारधारात्मक प्रचार

तकनीकी विकास के साथ नक्सली संगठन भी अपने प्रचार-प्रसार में डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल एप्लिकेशन, और एन्क्रिप्टेड चैट प्लेटफॉर्म के जरिए वे युवाओं तक अपनी विचारधारा तेजी से पहुंचा रहे हैं। यह डिजिटलीकरण नक्सली संगठनों को और अधिक संगठित, सुव्यवस्थित और सक्रिय बनाता है, जिससे सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। साथ ही, यह प्रचार युवाओं के मनोबल को प्रभावित कर हिंसा और अलगाव की भावना को बढ़ावा देता है।

इन चुनौतियों को समझकर ही प्रभावी नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी विकास और शांति स्थापित कर सकें।

10. निष्कर्ष (Conclusion)

नक्सलवाद के संदर्भ में आदिवासी युवाओं की भूमिका में 2015 से 2025 की अवधि में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। यह बदलाव मुख्यतः उनकी सोच में आए बदलाव, शिक्षा के प्रसार, और सामाजिक-सांस्कृतिक संवाद की वजह से संभव हुआ है।

सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में आदिवासी युवाओं की सोच

आदिवासी युवाओं ने अब नक्सली हिंसा की बजाय विकास और मुख्यधारा की ओर लौटने का रास्ता अपनाया है। वे न केवल अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और रोजगार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बल्कि अपने समुदाय के कल्याण में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यह बदलाव नक्सलवाद के खिलाफ सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देता है और हिंसा को कम करने में मददगार साबित हो रहा है।

शिक्षा, संवाद और सशक्तिकरण की भूमिका

शिक्षा ने युवाओं के दृष्टिकोण को व्यापक और प्रगतिशील बनाया है, जिससे वे नक्सली विचारधारा से दूर होकर नए अवसरों की खोज में लगे हैं। साथ ही, संवाद के माध्यम से सरकार, सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास स्थापित हो रहा है, जो सामूहिक विकास की नींव है। युवाओं का सशक्तिकरण, विशेषकर कौशल विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों के जरिए, उनके आत्मनिर्भर बनने और मुख्यधारा में पूर्ण रूप से समाहित होने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

सतत प्रयासों की आवश्यकता

हालांकि, इस सकारात्मक बदलाव के बीच अभी भी कई चुनौतियाँ और अवरोध मौजूद हैं। इसलिए, सतत और समन्वित प्रयास आवश्यक हैं ताकि विकास योजनाएँ प्रभावी रूप से लागू हों, प्रशासनिक कमजोरियाँ दूर हों और नक्सली संगठनों के डिजिटल प्रचार का मुकाबला किया जा सके। इसके लिए सरकार, समाज और नागरिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा ताकि आदिवासी युवाओं को स्थायी रूप से मुख्यधारा में जोड़ा जा सके और क्षेत्र में शांति और समृद्धि स्थापित हो।

इस प्रकार, यह अध्ययन नक्सलवाद और आदिवासी युवाओं के बीच बदलते संबंधों को समझने में मदद करता है और भविष्य की नीतिगत दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करता है।

11. सुझाव (Suggestions/Recommendations)

नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा में समाहित करने और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव अत्यंत आवश्यक हैं:

11.1 स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाना

स्थानीय स्तर पर आदिवासी समुदायों के नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए ताकि वे विकास योजनाओं के सही क्रियान्वयन और युवाओं के सशक्तिकरण में अग्रणी भूमिका निभा सकें। इससे स्थानीय लोगों में स्वामित्व की भावना जागेगी और नक्सली प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

11.2 रोजगार के अवसरों को बढ़ाना

युवाओं को स्थायी और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, खासकर कृषि, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्र में। यह आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और नक्सलवादी आंदोलन से दूर रखेगा।

11.3 शिक्षा व डिजिटल साक्षरता में निवेश

आदिवासी युवाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट के माध्यम से युवा नई जानकारियाँ और अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपने कौशल में सुधार कर बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें।

11.4 संवाद-आधारित नीतियों को बढ़ावा देना

सरकार, प्रशासन, सुरक्षा बल और आदिवासी समुदाय के बीच खुला और पारदर्शी संवाद स्थापित करना आवश्यक है। संवाद के माध्यम से विश्वास की कमी दूर हो सकती है और सामूहिक विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। संवाद-आधारित नीतियाँ स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं को बेहतर समझने और उनका समाधान निकालने में सहायक होती हैं।

इन सुझावों को प्रभावी रूप से लागू करने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी विकास और शांति सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे आदिवासी युवाओं का मुख्यधारा में सफल समावेश संभव होगा।

12. संदर्भ सूची (References/Bibliography)

1. Ministry of Home Affairs, Government of India. (2022). *Annual Report on Left Wing Extremism*. New Delhi: MHA Publications.
2. National Crime Records Bureau (NCRB). (2023). *Crime in India Report*. New Delhi: NCRB.
3. NITI Aayog. (2021). *Developmental Initiatives in Tribal Areas: A Review*. New Delhi: NITI Aayog.
4. Singh, A. (2020). *Naxalism and Tribal Development in India*. Journal of Social Science, 45(3), 112-130.
5. Sharma, R. (2019). *Role of Education in Countering Naxal Violence*. International Journal of Tribal Studies, 12(2), 89-102.
6. Das, S. & Kumar, P. (2021). *Digital Propaganda and Left-Wing Extremism: Challenges for Security*. Defence Studies Quarterly, 18(1), 54-69.
7. Roy, M. (2018). *Adivasi Youth and Naxalism: A Socioeconomic Perspective*. New Delhi: Sage Publications.
8. Indian Express. (2023, March 15). “Government’s New Initiatives in Naxal-Affected Regions.” Retrieved from https://indianexpress.com
9. The Hindu. (2024, January 10). “Digital Tools Fueling Naxal Recruitment.” Retrieved from https://thehindu.com
10. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED). (2022). *Annual Report*. New Delhi: TRIFED.